IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय उद्योग धन्धों की स्थिति (1757 ई0 – 1813 ई0)

डा0 अवधेश कुमार
असिस्टेन्ट प्रोफेसर –इतिहास
डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय,
सन्त रविदास नगर, भदोही

मुगल साम्राट औरंजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इसी क्रम में मुर्शीद खुली खां ने बंगाल में एक अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1756 ई0 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात सिराज–उद्–दौला बंगाल का नवाब बना। सिराज–उद्– दौला के शासनकाल तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों तथा डचों को पूर्णतया पराजित कर दिया था। उस समय तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केवल फ्रांसीसी ही बचे थे। 1756 ई0 में जब फ्रांस तथा इंग्लैण्ड के मध्य सप्त वर्षीय युद्ध प्रारम्भ हुआ तब उसका प्रभाव भारत में भी दिखाई पड़ा। इस युद्ध के कारण अग्रेंज तथा फ्रांसीसी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे।

सप्त वर्षीय युद्ध प्रारम्भ होने के पश्चात फ्रांसीसियों तथा अग्रंजो ने बंगाल में अपनी अपनी बस्तियों की किले बन्दी करना प्रारम्भ किया। बंगाल के नवाब ने इस किलेबन्दी को रोकने का आदेश दिया जिसे फ्रांसीसियों ने तो मान लिया किन्तु अंग्रेज नही माने। जिससे बंगाल के नवाब ने 20 जून 1756 ई0 को अंग्रेजो पर आक्रमण कर दिया। [1] इसके पश्चात कई अंग्रेजों को कैद करके एक छोटे से कमरें में बन्द कर दिया गया जिसे कुछ इतिहासकारों द्वारा कलकत्ता के ब्लैक होल की घटना के रूप में वर्णित किया गया है। इस घटना के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन कार्यरत कलकत्ता तथा मद्रास काउसिल ने मिलकर के नवाब के साथ अली नगर की सन्धि करके पुन : अपनी बस्तियों स्थापित किया तथा विशेषाधिकारों को भी वापस प्राप्त किया। इस घटना के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के नवाब के विरूद्ध षडयंत्र रचना प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप 1757 ई0 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराज –उद–दौला की पराजय हुई तथा बंगाल में ब्रिटिश शासन के स्थापित होने की प्रकिया प्रारम्भ हो गई। 1764 ई0 के बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में भूराजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। [2]

बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बंगाल में पहले से चली आ रही भूमि सम्बन्धी व्यवस्था को समाप्त करके नई भू–राजस्व पद्धति लागू करने का निर्णय लिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां के समय से चली आ रही व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किये। यद्यपि किपहले से चली आ रही व्यवस्था में बंगाल के नवाब द्वारा जमींदारों से पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जाता था किन्तु उनके द्वारा जमीदारों को हटाया नही जाता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा 1760 ई0 में मीर कासिम से वर्धमान और मेदनीपुर जिले लेने के पश्चात लागू की गई नई भू–राजस्व प्रणाली में जमींदारों के परम्परागत अधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया तथा उनकी जमीदारियों को नीलाम करके बेच दिया गया। बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर श्री हैरी वेरेलस्ट ने इस संबंध में लिखा – ''वर्धवान और मैदिनीपुर के इलाकों में, जो सम्पत्ति और क्षेत्राधिकार, दोनों दृष्टियों से 1760 में मीर कासिम द्वारा कम्पनी को सौंप दिए गए, ये बुराइयों जो मूरं (मूर से मतलब यहाँ मुस्लिम सरकार से है) सरकार की कुनीतियों से आवश्यक रूप से पैदा हुई थी, किसी भी तरह नहीं घटी। इसके विपरीत 1762 में एक ऐसी योजना बनी, जिससे इस इलाके का निश्चित सत्यानाश हो जाए । जमीनें नीलाम से 3 साल की अल्प अवधि के लिए बेच दी गई। चरित्रहीन और धनहीन लोगों ने बोली बोली। एक तरफ पहले के कुछ किसान, जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे, ज्यादा बोली बोल गए, तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों ने बोली बोली, जिन्हें कुछ खोना नहीं था क्योंकि किसी भी हालत में उन्हें यह आशा थी कि फौरन कब्जा मिलेगा। इस प्रकार से मुसीबत में पड़े हुए लोगों पर असंख्य बदमाश लूटमार के लिए छूट गए, जो लूट से पहले साल का भुगतान किसी प्रकार कर ले गए ।''[3]

इस प्रकार से भारत में प्राप्त राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग करके बंगाल में चले आ रहे परम्परागत जमींदार वर्ग को समाप्त करना प्रारम्भ किया। कम्पनी के शासन के अधीन बंगाल का व्यापार भी हतोत्साहित हुआ तथा बंगाल में किसानों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इन्ही प्रतिकूल परिस्थितियों में 1770 ई0 में बंगाल में भयंकल अकाल पड़ा।[4]

1772 ई0 में बंगाल के नवाब वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक नई भू–राजस्व प्रणाली जिसे पंचसाला पद्वति कहा गया, को लागू किया गया। जिसके माध्यम से कम्पनी ने अपने आय को बढ़ाने का प्रयास किया इस नई भू–राजस्व प्रणाली के फलस्वरूप बंगाल की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने प्रारम्भ हुई– ''1770 के दुर्भिक्ष के बावजूद, जिससे बंगाल का अवर्णनीय सत्यानाश हुआ था । एक के बाद एक तरह–तरह के तरीकों से, जिनमें से बहुतेरे खतरनाक थे, कथित विनियोग जबरदस्ती जारी रखा गया। इसी इलाके से वसूल किए हुए राजस्व से बंगाल के माल तथा यूरोप के माल की बिक्री से तथा एकाधिकारों से प्राप्त धन कभी 10 लाख पौंड से कम नहीं बैठता था, बल्कि अक्सर 12 लाख पौंड के लगभग होता था। इस प्रकार कम से कम 10 या 12 लाख पौंड का माल यूरोप भेजा जाता था, जिसका कोई मुआवजा नहीं मिलता था। बंगाल से कम्पनी के हिसाब में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख पौंड चीन भेजा जाता था और उस

धन से प्राप्त सारी उपज सीधे व्यापार में चीन से यूरोप जाती थी। इसके अलावा शान्ति के समय बंगाल भारत की दूसरी प्रेसिडेंसियों को मदद पहुंचाता है, जो अपनी व्यवस्था के अनुसार आमदनी नहीं दिखा पाते..।

''बंगाल और इंग्लैंड के बीच लेन–देन का, हम इसे व्यापार नहीं कह सकते, हिसाब लगाने पर राजस्व से कथित विनियोग की पद्धति के हानिकार प्रभाव अच्छी तरह दिखाई पड़ जाते हैं। यदि उस दृष्टि से देखा जाए कि कम्पनी देश से जो कुछ भी माल निर्यात करती है, तो वह कोई विनिमय नहीं है, बल्कि वह बिना किसी प्रतिदान या भुगतान के लिया हुआ माल है।

''देश के बाहर जानेवाले दोहन की विपुलता और उसका प्रभाव हम इस तरह से और भलीभांति समझ सकते हैं कि आपकी कमेटी ने बंगाल के राजस्व के उन अंशों को चीन और यूरोप के लिए कम्पनी के अपने विनियोगों में लगाने की सोची है– जो रकम असैनिक सरकार को कायम रखने के लिए खर्च होती है, देश के लोग लगभग सम्पूर्ण रूप से उसके हिस्से से वंचित होते हैं, जैसे कि वे राजस्व की मुख्य वसूलियों से भी कोई लाभनहीं उठा पाते। बहुत थोड़े अपवादों के सिवा भारतीय केवल यूरोपियों के नौकरों और एजेन्टों के रूप में या वसूली के निचले विभागों में नियुक्त होते हैं, ऐसा भी इस कारण कि उनकी सहायतों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता।''[5]

1772 ई0 में मुगल साम्राट आलम द्वितीय के दिल्ली की गद्दी में बैठने के पश्चात मराठों ने उनसे इलाहाबाद तथा कड़ा प्राप्त कर लिया।[6] 1772 ई0 तक आते आते ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा बंगाल का दोहन करके कम्पनी ने पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित किया। बंगाल से प्राप्त होने वाली चांदी का उपयोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था।[7] ईस्ट इण्डिया कम्पनी की औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर होनी प्रारम्भ हो गई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीतियों का मूल उद्देश्य भारतीयों राज्यों को अपने अधीन करना था। इसलिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बनारस के राजा चेत सिंह को हटाने के लिए उनसे अत्यधिक धन की मांग की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय राज्यों की प्रभुसत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से नैतिकता की सारी सीमाऐं लाघीं। कम्पनी के द्वारा चेत सिंह को हटाए जाने का विरोध करते हुए फिलिप फ्रासिस ने लिखा – ''इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि राजा अवश्य सरकार की शक्ति के आगे नतमस्तक रहे, और मैं बोर्ड के किसी भी सदस्य की तरह सरकार के अधिकार का समर्थन करने के लिए तैयार रहूंगा, बशर्ते कि इसकी शक्ति न्याय का आधार हो । मैंने पहले ही से इस बात पर सन्देह प्रगट किया कि पहले हमने राजा को जो शतें दी थीं, और जिन पर वह राजो हुए थे, उन शर्तों के अलावा मांगों का हमें अधिकार नहीं हैं। उन शर्तो के सम्बन्ध में मेरा बराबर यह विचार रहा है कि वे मौलिक तत्त्व है, जिनके अनुसार वह अपनी जमीं–दारी का मालिक बना है। हमें राजा से उन शर्तों के आगे कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार से प्रबलतर शक्ति की इच्छा के अनुसार राजा पर मांगें बढ़ाई जा सकती हैं, तो न तो उसका कोई अधिकार रह जाता है न सम्पत्ति। कम

से कम उसके अधि–कार और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। हम 5 लाख के बदले 50 लाख मांगें, इस पर या तो वह इन्कार करेगा या वह न दे पाएगा। इसका तात्कालिक नतीजा यह होगा कि जमींदारी जब्त हो जाएगी।''[8]

ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा अवध के नवाब के मध्य 1801 ई0 की सन्धि के माध्यम से कम्पनी को रूहेलखण्ड, दोआब तथा गोरखपुर का क्षेत्र प्राप्त हुए।[9] यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। उत्तर भारत में बुनकरी एक महत्वपूर्ण धन्धा था। औपनिवेशिक शासन की नीतियों से रेशमी तथा सूती वस्त्रों का उत्पादन घटने लगा। इंग्लैण्ड को भेजे जाने वाले निर्यात में कमी आने लगी। 19 वीं शताब्दी के आते आते भारतीय उद्योग धन्धों पर कम्पनी के शासन का दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा। भारतीय उत्पादों पर लगाये जाने वाले निषेधात्मक शुल्कों के कारण भारतीय उद्योग धन्धो का ह्रास होने लगा। भारतीय उद्योग धन्धों की स्थिति के सबन्ध में लोकसभा समिति के समक्ष जॉन रैकिंग ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा– ''क्या आप बता सकते हैं कि ईस्ट इंडिया हाउस में कपड़े पर मूल्य का कितना प्रतिशत शुल्क है ?''

–''कैलिको कहलाने वाले कपड़े को मंगाने पर 3 पौंड 6 शि० 8 में० प्रतिशत शुल्क है और यदि वे देश में खपाए जाएं, तो उस पर इसके अलावा 68 पोंड 6 शि० 8 पं० प्रतिशत शुल्क है।'' –''मलमल नाम का एक और कपड़ा है, जिसे मंगाने पर 10 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है और यदि वह देश में खपाया जाय, तो प्रतिशत 27 पौंड 6 शि० 8 पै० शुल्क और लग जाता है।''

–''एक तीसरा वर्ग रंगीन माल का है, जिनका इस देश में इस्तेमाल वर्जित है, उसे मंगाने पर प्रतिशत 3 पौंड 6 शि० 8. पं० का शुल्क है। ये माल केवल चालान के लिए ही हैं।''

– ''संसद के इस अधिवेशन में कुल शुल्कों पर एक नया 20 प्रतिशत शुल्क और बढ़ा है, जिससे देश में खपाए जाने वाले कैलिको पर शुल्क प्रतिशत 78 पौंड 6 शि० 8 वें० हो जाएगा और इसी प्रकार देश में खपाए जाने वाली मलमल के लिए शुल्क 31 पौंड 6 शि० 8 पं० होगा ।''

इन निषेधात्मक शुल्कों के असली उद्देश्य को छिपाया भी नहीं जाता था। उसी गवाह रैकिंग ने और आगे कहा– ''मैं इसे अपने देश के उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए एक संरक्षक शुल्क मानता हूँ।''[10]

इस प्रकार से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने नीतियो के माध्यम से भारत से होने वाले प्राचीन काल से रेशमी तथा सूती वस्त्रों के निर्यात को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। प्राचीन काल से ही भारतीय रेशमी तथा सूती वस्त्रों की यूरोपीय बाजारों में काफी मांग रहती थी किन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उत्पादों पर निषेधात्मक शुल्क लगाकर उनके निर्यात को हतोत्साहित किया जिससे भारत तथा इंग्लैण्ड के मध्य होने वाले व्यापार से भारत को प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित किया जा सके। ईस्ट

इण्डिया कम्पनी ने अपनी नीतियों से न केवल भारतीय उद्योग धंन्धों के उत्पादन में कमी लाने का प्रयास किया अपितु इंग्लैण्ड में तैयार उत्पादों को भारतीय बाजारों में बेचने का प्रयास करके आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश की।

संन्दर्भ

1. मजुमदार, आर0सी0 (सं0),*हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल खंड आफ द मराठा सुप्रीमेसी,* भारतीय विद्या भवन, बम्बई, 1977, पृ0 655–665
2. प्रसाद, ईश्वरी, *इण्डिया इन द एटींथ सेन्चुरी,* इलाहाबाद, 1973 पृ0 97
3. बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर थी हेरी वेरेलस्ट द्वारा लिखित वियु आफ दि राइले एटसेट्रा आफ दि इंगलिश गवर्नमेन्ट इन बेंगाल, लन्दन 1772, पृ० 70 दत्त, रोमेश, *इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया,* खंड–1, नई दिल्ली, (पुनर्मुद्रण) 2006, पृ0 29 में उद्धृत
4. मजुमदार, आर0सी0 (सं0), *पूर्वोक्त,* पृ0 357
5. सिलेक्ट कमेटी को नवी रिपोर्ट, 1783, पृ0 55 दत्त, रोमेश, *पूर्वोक्त,* पृ0 46–47 में उद्धृत
6. एटकिंशन, सी.यू.,ए *कलेक्शन आफ ट्रीटीज, इन्गेजमेन्ट्स एण्ड सनदस,* 14 खण्ड कलकल्ता, खण्ड।। 1863, (पुनर्मुद्रण,) 1909 पृ0 8 – 10
7. ट्रैक्ट बाइ जेम्स स्टुवर्ट, लन्दन, 1772, एस. भट्टाचार्या, कुमार तथा देसाई, *कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ इण्डिया,* खण्ड।।, पृ0 289, अल्वी, सीमा, *द एटीन्थ सेंचुरी इन इण्डिया,* आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2002 पृ0 72 में उद्धृत
8. सिलेक्ट कमेटी की दूसरी रिपोर्ट 1782. पृ० 465. दत्त, रोमेश, *पूर्वोक्त,* पृ0 49 में उद्धृत
9. मजुमदार, आर0सी0 (सं0), *पूर्वोक्त,* पृ0 523
10. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मामलो (1813) पर गवाहियां, पृ० : 463, 467 दत्त, रोमेश, *पूर्वोक्त,* पृ0 184 में उद्धृत